VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

G20 ITALIA 2021

BRICS INDIA 2021

कोविड-19 पर जी-20 और ब्रिक्स की प्रतिक्रिया

प्रस्तावना

कोविड-19 का प्रभाव विश्व स्तर पर विभिन्न विकास संकेतकों में गंभीर रूप से पड़ा है, हालांकि इसका सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक विकास क्षेत्र पर पड़ा और इस क्षेत्र के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। लगभग सभी देशों ने व्यवस्थित रूप से लॉकडाउन लगाया क्यूंकि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था, जिससे नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट आई है। प्रभावित देशों को वापस पटरी पर लाने के लिए, कई वैश्विक बहुपक्षीय संगठन जैसे जी-20, ब्रिक्स और जी-7 भव्य घोषणाओं के साथ आगे आए है, जो सकारात्मक विकास की रिकवरी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नागरिकों को उनकी पूर्व-कोविड स्थिति और प्रभावित देशों में संसाधनों की आर्थिक मांग को पुनः स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता पैकेज शुरू किए गए हैं। कई ग्लोबल नॉर्थ देशों ने मांग को प्रोत्साहित करने के लिए उछाल लगाई है और परिस्थितियों का निर्माण किया है ताकि व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सके। सरकारों द्वारा मौद्रिक, राजकोषीय और रोजगार नीतियों में बदलाव पर काम किया जा रहा है ताकि ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा सकें जो प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विकास के पूर्व-कोविड स्तरों तक पहुँचने में मदद करे। इसके साथ ही, जी-20 स्वास्थ्य सेवा संरचना में सुधार को बहुपक्षीय संगठनों के लिए आधारशिला के रूप में देखता है क्योंकि कोविड संकट ने देश की स्वास्थ्य संचालन की भयंकर विफलताओं को प्रकट किया था। स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करने, चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा सामग्री में अधिक निवेश की आवश्यकता है जो भविष्य में कोविड के बदलते रूपों को कम करेगा । आर्थिक उत्साह और युद्ध-स्तर पर स्वास्थ्य संरचना (पहली और दूसरी लहर के बाद) में कमी एक तीव्र नीति और कार्यावयन की मांग करती है जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों में भविष्य में होने वाली आर्थिक गिरावट को रोक सकती है। इससे जुड़ी, कमियों को दूर करने में सिविल सोसाइटी का सहयोग सबसे ज्यादा रहा है। वैश्विक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन (कोविड के जवाब में) के पहले दिन से उनमें से अधिकांश सिविल सोसाइटी संगठन अपने नेटवर्क और गठबंधनों को जोड़कर वैश्विक मंचों पर तेजी से कार्य करने का दबाव बना रहे हैं। विश्व स्तर पर वे लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए भोजन की प्राथमिकता का समर्थन करते रहे हैं, संकटग्रस्त परिवारों का सहयोग करते रहे हैं और जरूरतमंदों और वंचित आबादी को दवा पहुँचाते हैं। हालाँकि, अंतिम सहायता सरकारों की ओर से आना आवश्यक है, जिस पर निश्चित रूप से वैश्विक बहुपक्षीय संगठनों द्वारा सहमति प्राप्त की जा सकती है क्योंकि उनमें से कई भविष्य में होने वाली महामारियों से बचाव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। इस प्रकार यह दस्तावेज़ इस बात का विश्लेषण है कि कैसे दो प्रभावशाली बहुपक्षीय संगठनों जी 20 और ब्रिक्स द्वारा कोविड -19 के प्रभावों को प्रबंधित किया गया है और ग्लोबल सिविल सोसाइटी से अपनी नीति में सम्मिलित करने के लिए सिफारिशें एकत्र करने का प्रयास करता है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल साउथ बहुपक्षीय संचालन में सुधार की मांग कर रहा है । इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, मैं अर्जुन फिलिप्स, प्रोग्राम मैनेजर, वाणी और हेनरिच बोएल स्टिफटंग को इस दस्तावेज़ में सहयोग करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

धन्यवाद
हर्ष जेटली,
सीईओ, वाणी

G20

विषय वस्तु

प्रस्तावना	iii
दुनिया भर में कोविड -19 की स्थिति	2
कोविड -19 पर जी 20 की प्रतिक्रिया	5
कोविड -19 के जवाब में जी 20 का व्याख्यान और फोकस	5
कोविड -19 के लिए जी 20 की वित्तीय प्रतिक्रिया	8
जी 20 द्वारा विकास प्रतिक्रिया	9
विकास के लिए जी 20 की कार्रवाई पर सिविल सोसायटी की प्रतिक्रिया	10
जी 20 के लिए सी 20 द्वारा मुख्य संदेश	10
कोविड -19 पर ब्रिक्स की प्रतिक्रिया	10
कोविड -19 प्रतिक्रिया के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का विकास वित्तपोषण	11
सामाजिक-आर्थिक अविकास के कारण कोविड -19 में वृद्धि	14
कोविड -19 के लिए देशभर में सिविल सोसाइटी की प्रतिक्रिया	14
निष्कर्ष	14

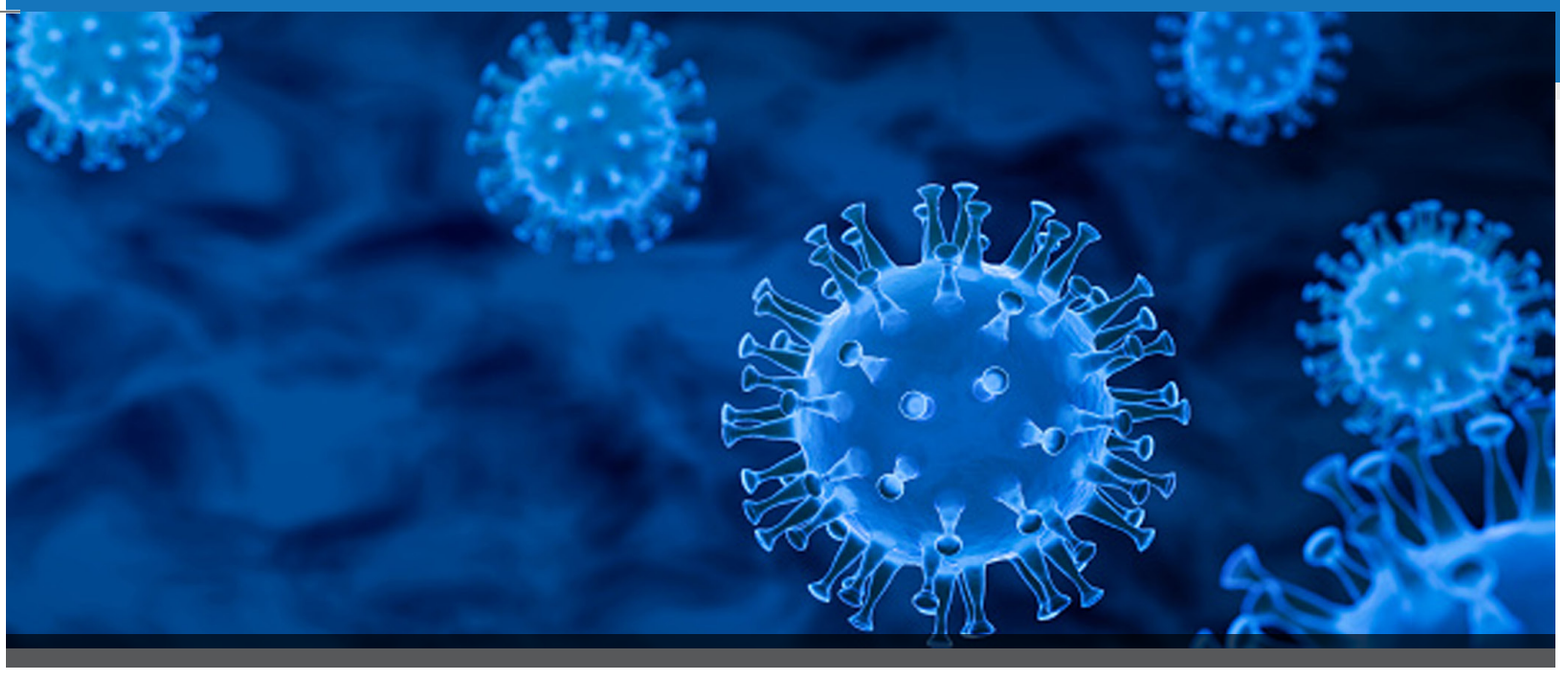

दुनिया भर में कोविड -19 की स्थिति

जब से कोविड -19 ने विश्व में दस्तक दी है, तब से दुनिया भर में एक विनाशकारी विध्वंस देखा गया है, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा आदि सभी विकास आयामों में स्पष्ट रूप से देखा गया । जब विश्व दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तो कोविड -19 ने प्रारंभिक 5 वर्षों में की गई सभी पहलो को उलट कर उनका मार्ग रोक दिया।[1] गंभीर रूप से यह सामाजिक तनाव को बढ़ाने और सामाजिक-विकास को अपरिवर्तनीय हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है।[2]

यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार - 2030 तक 41 से 169 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में हो सकते हैं, मानव विकास के निम्न और मध्यम स्तर वाले देशों में, जिनमें 20 और 83 मिलियन महिलाएं और लड़कियां शामिल होंगी । अनुमानित 24 से 86 मिलियन लोग निम्न मानव विकास समूह वाले देशों से होंगे। निम्न और मध्यम मानव विकास वाले देशों में गरीबी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या एक 'कोविड बेसलाइन' के तहत 626 मिलियन और 'उच्च क्षति' परिदृश्य में 753 मिलियन के बीच बढ़ जाएगी। कोविड -19 'नो कोविड' दुनिया की तुलना में 2030 तक देशों के इस सबसेट में कुपोषण से पीड़ित लोगों की संख्या में 12.8 मिलियन की वृद्धि कर सकता है। कुपोषित बच्चों की संख्या में 1.6 मिलियन की वृद्धि होगी, 2030 तक कुल 57.5 मिलियन बच्चे कुपोषित हों जायेंगे। कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या 'उच्च क्षति' परिदृश्य के तहत 2030 तक बढ़कर 60.5 मिलियन से अधिक हो सकती है।[3]

लेकिन यह महामारी अभूतपूर्व है क्योंकि यह एक स्वास्थ्य आघात से बढ़कर एक आर्थिक और सामाजिक संकट लेकर आई है। सोशल डिस्टेंसिंग और गैर-जरूरी कामों में ठहराव ने मानवीय गतिविधियों को धीमा कर दिया है। इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि 2020 की दूसरी तिमाही में, काम के घंटो में 195 मिलियन पूर्णकालिक श्रमिकों के बराबर गिरावट आएगी। अन्य संकटों के विपरीत, दो मुख्य चैनलों के माध्यम से रोजगार प्रभावित हो रहा है। श्रम की मांग में कमी, मानव गतिविधियो में कमी और धन प्रभाव से वैश्विक मंदी की वजह से आएगी । श्रम आपूर्ति में एक अल्पकालिक गिरावट कई देशों में गैर-आवश्यक उत्पादक गतिविधियों के निलंबन से आती है और यह व्यापक आर्थिक नीतियो में बेरोजगारी में वृद्धि करती है। लेकिन इसका प्रभाव कुल मांग में सामान्य गिरावट से अलग हैं जो आमतौर पर उपभोग को प्रभावित करती है और आर्थिक गतिविधियो को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां मानव संपर्क को कम करने और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियो पर आधारित हैं। ये प्रभाव अलग-अलग प्रसार पैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं।

[1] UN report finds COVID-19 is reversing decades of progress on poverty, healthcare and education | UN DESA | United Nations Department of Economic and Social Affairs

[2] UN SDGs under threat as poverty and inequality rise | World Economic Forum (weforum.org)

[3] LeavingNoOne_impact_of_COVID_19_on_the_SDGs.pdf (undp.org)

आर्थिक रूप से प्रभावित देशों को स्वास्थ्य से पहले, आय प्रभाव प्रभावित करते हैं, और स्वास्थ्य संकट समाप्त होने के बाद भी यह जारी रहते हैं। यहां तक कि जब श्रम आपूर्ति पर प्रतिबंध हटा दिया जाता है, तब भी काम के घंटे कम हो सकते हैं - सुधार की धीमी गति के कारण या उपभोक्ता मांग में कमी के कारण।[4]

ओईसीडी के अनुसार, कई निम्न और मध्यम आय वाले देश पहले ही मौजूदा संकट और दीर्घकालीन विकास के लिए वित्तपोषण में सीमित वित्तीय क्षेत्र का सामना कर रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और सामाजिक आर्थिक नुक्सान से स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक राहत और नकदी के लिए बड़े और तत्काल सार्वजनिक खर्च की आवश्यकता होती है, न कि संकट से सुधार के लिए खर्च की आवश्यकता होगी। बढ़ती खर्च की ज़रूरतों और घटते राजस्व के साथ, कई देशों में सार्वजनिक ऋण बड़े पैमाने पर बढ़ने की संभावना है। ऋण संकट का जोखिम विशेष रूप से नाजुक क्षेत्र और तेल-समृद्ध देशों में निश्चित रूप से होता है, जहां सार्वजनिक ऋण एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक भाग और महंगा होता है, जिसे अक्सर निजी लेनदारों द्वारा गैर-रियायती शर्तों पर बढ़ाया जाता है और पुनर्भुगतान के साथ कभी-कभी रणनीतिक प्राकृतिक सम्पतियों से जुड़ा होता है।

ऋण की लागत में वृद्धि से उपलब्ध वित्तीय क्षेत्र में और कमी आएगी। कोविड -19 महामारी के परिणामस्वरूप देशों के सार्वभौमिक क्रेडिट स्कोर में मिश्रित जोखिम मूल्यांकन और गिरते सार्वजनिक ऋण की लागत को और बढ़ा सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए देशों की क्षमता को सीमित कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, उपलब्ध वित्तपोषण (आपूर्ति) और खर्च की जरूरतों (मांग) में वर्णित विस्तार (अंतराल) ओईसीडी में पहचाने गए, दीर्घकालीन विकास वित्त के तथाकथित "सीजर इफ़ेक्ट" को बढ़ाता है जो उपलब्ध वित्तपोषण में एक साथ गिरावट और एसडीजी खर्च की जरूरतों में वृद्धि को प्रस्तुत करता है।[5]

यूएनडीईएसए (UNDESA) के अनुसार कोविड -19 महामारी की शुरुआत के साथ:

भूख और खाद्य असुरक्षा से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही थी। 2019 में लगभग 690 मिलियन लोग कुपोषित थे, जो 2014 से लगभग 60 मिलियन अधिक थे। 2019 में लगभग 2 बिलियन लोग मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित थे।

जलवायु परिवर्तन अनुमान से कहीं अधिक तेजी से हो रहा था। वर्ष 2019 रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म और 2010 से 2019 के सबसे गर्म दशक का अंत था, जो अपने साथ महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर जंगल की आग, तूफान, सूखा, बाढ़ और अन्य जलवायु आपदाएं लेकर आया था। सदी के अंत तक वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 3.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की राह पर था।

बिगड़ता पर्यावरण: उपभोग और उत्पादन स्वरूप टिकाऊ नहीं थे; सतत कमी, पर्यावरण में गिरावट, CO2 सैचुरेशन और अम्लीकरण के कारण; वनो में खतरनाक रूप से गिरावट जारी है; संरक्षित क्षेत्र अपनी जैविक विविधता के कारण केंद्रित नहीं थे, और प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ था।

देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता बढ़ती रही थी। वयस्क श्रमिकों की तुलना में युवा श्रमिकों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी हो गई थी और बिजली तक पहुंच के बिना 85 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। तीन चौथाई अविकसित बच्चे केवल दो क्षेत्रों में रहते थे: दक्षिणी एशिया (39 प्रतिशत) और उप-सहारा अफ्रीका (36 प्रतिशत)।[6]

[4] covid-19_and_human_development_0.pdf (undp.org)
[5] The impact of the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance (oecd.org)
[6] UN/DESA Policy Brief #81: Impact of COVID-19 on SDG progress: a statistical perspective | Department of Economic and Social Affairs

प्रवृत्तियों को उलटना

ये प्रवृतियाँ बदली जा सकती हैं यदि देश सबसे कमजोर वर्ग को सहयोग करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को कोविड -19 से मिले अवसर का उपयोग करते हुए लागू करे । हालाँकि 2020 में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रसार को अस्थायी उपायों के रूप में लिया गया था, उम्मीद है कि अब संरचना के साथ ये कार्यक्रम गरीबों के लिए सहायता प्रदान करेंगे और उन्हें गरीबी से बाहर निकलने में मदद करेंगे। बिग डेटा और मशीन लर्निंग इन प्रयासों में मदद कर सकते हैं, जिससे सरकारों को जरूरतमंद लोगों की बेहतर पहचान करने और उन्हें लक्षित करने में मदद मिल सकती है।[7] एक ऐसा सुधार कार्यक्रम बनाया जाये जो समावेशी, टिकाऊ और लचीला हो, जिसमे सार्वजनिक नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता हो । कोविड -19 से उभरने की प्रभावशीलता और लचीलापन इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करेगा कि यह कितना व्यापक और सामाजिक रूप से समावेशी है। विशेष रूप से, इस संकट के दौरान जो असमानताएँ बड़ी हैं, उससे आर्थिक और सामाजिक परिणाम लंबे समय तक प्रभावित होंगे, जो एक वास्तविक जोखिम है, विशेषतः असमान रूप से प्रभावित समूहों जैसे कि युवा, महिलाएँ, छोटे और सूक्ष्म उद्यम जो दुनिया में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करते हैं।[8]

हालाँकि, यह देखना बाकी है कि नीतिगत कार्रवाई किस प्रकार की जाये, विशेषकर जब जलवायु बदल रही है और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।[9] दूसरे, समावेशी सुधार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत कार्रवाई में लिंग विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि 2021 में लाखों लड़कियां स्कूल नहीं जा पाई हैं और घरेलू हिंसा की दर आसमान छू रही है। जो महिलाएं महामारी के दौरान अपनी नौकरी पर बने रहने में सक्षम रही हैं, उन्हें अभी भी विकासशील और विकसित देशों में समान रूप से काम के लिए सबसे कम वेतन मिलता है। इस प्रकार, लिंग वेतन अंतर को कम करने में लगभग 163 साल लग सकते हैं - इससे भी अधिक अगर महिलाएं नौकरी करना छोड़ती हैं।[10] दुनिया भर में युवा जनसंख्या के लिए भी यही सच है, जहां छंटनी और बेरोजगारी में तेज वृद्धि ने असहनीय मानसिक तनाव पैदा किया है ! इसके लिए जी-20 को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक एकीकृत वैश्विक संचालन प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो सकती है।[11]

तीसरा, कोविड -19 से लड़ने के लिए असमानता के बढ़ते प्रभाव को बहुआयामी आर्थिक नीति की आवश्यकता होगी जो एक सूचित मौद्रिक और राजकोषीय नीति पर केंद्रित हो और जो समावेशी विकास की ओर ले जाए।[12]

बहुपक्षीय संचालन प्रणाली में सुधार

चौथा, बहुपक्षीय संगठनों, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन के कामकाज को फिर से व्यवस्थित करने और उसमे सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे ग्लोबल नार्थ के संरक्षण के तहत एक द्विदलीय मंच पर बने रहने की अनुमति मिले, जो ग्लोबल साउथ के साथ टीके, चिकित्सीय निदान साझा करने के लिए मजबूती से खड़े हो।[13] इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि बहुपक्षीय संगठनों की गलतियों[14] को दूर करने और वैश्विक निर्णय लेने वाले मंचों पर ग्लोबल साउथ देशों को अधिक स्थान प्रदान करने के लिए एक समन्वित और संगठित तरीके से काम करने की आवश्यकता है।[15] [16]

कोविड -19 के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की परिकल्पना करना

अटलांटिक काउंसिल के एक पेपर के अनुसार- जी-7 को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और यात्रा को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने, कर्मचारियों को काम पर वापस लाने के साथ-साथ ग्लोबल सप्लाई चेन (वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं) को साफ रखने के लिए सामान्य विश्व मानकों को विकसित करने के लिए मंच के रूप में काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कार्गो कीटाणुमुक्त करने के लिए मानक स्थापित करके, विश्व के नेता आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वास बढ़ा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं। जी-20 को आपूर्ति-श्रृंखला स्वच्छता के लिए सामान्य मानकों को अपनाने का भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके लिए चीन की ओर से पारदर्शिता के लिए एक स्पष्ट और निश्चित प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। चीन से खरीदारी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को पुनर्जीवित करने में बहुत मदद करेगी, लेकिन केवल जी-7 के भीतर ही सामान्य मानकों को प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदलने के अलावा, जी-7 और जी-20 के सदस्यों को विकासशील विश्व के लिए राहत उपायों की

7 Long-run impacts of COVID-19 on extreme poverty (brookings.edu)
8 Remarks by ILO Director-General Guy Ryder109th International Labour Conference: Global agreement reached at ILO Conference on action for COVID-19 recovery
9 Global COVID-19 recovery plans aren't very green, analyses show - Axios
10 Why Do G20 Need a Global Gender-Responsive COVID-19 Recovery? (globalcitizen.org)
11 Youth and COVID-19: Response, recovery and resilience (oecd.org)
12 COVID-19 and Global Inequality – IMF F&D
13 Making trade multilateralism fit for purpose after COVID-19 | UNCTAD
14 Why International Institutions Failed to Contain the Coronavirus Pandemic (foreignaffairs.com)
15 Global and regional funding shifts | by OTT | TPA landscape scan and evaluation | Jun, 2021 | Medium
16 Don't expect miracles from the multilaterals (brookings.edu)

व्यवस्था करनी चाहिए। जी-20 ने पहले ही ऋण राहत पर समन्वय करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके लिए अभी और अधिक करना होगा और 2021 तक राहत उपायों का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। चीन को बीआरआई संरचना निवेश के कारण भारी ऋणी देशों को ऋण राहत का विस्तार करना चाहिए।[17]

एक रिपोर्ट के अनुसार "लंबी अवधि में कोविड -19 से निपटने के लिए : इस महामारी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कैसे मजबूत किया जाए", निम्नलिखित प्रयासों की आवश्यकता है:-

- अधिक से अधिक वित्तीय संसाधनों के लिए प्रतिबद्धता: अमीर देशों के स्तर पर टीकाकरण के लिए पूरी दुनिया को लगभग 11 बिलियन खुराक की आवश्यकता है, अब तक खर्च की गई लगभग राशि 35 बिलियन से 50 बिलियन यूएस डॉलर की लागत से अधिक है ।
- गरीब देशों के लिए स्थिर आपूर्ति धाराएं स्थापित करें और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने में मदद करें ताकि वे वैक्सीन रोलआउट की योजना बना सकें और उसे प्रभावी ढंग से लागू कर सकें !
- जीनोमिक सिक्वेंसिंग सहित ग्लोबल सर्विलेंस (वैश्विक निरिक्षण) को मजबूत करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीतियां और वित्त पोषण विकसित करना
- वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए संस्थागत सुधारों के पैकेज पर सहमती हो और दुनिया को भविष्य के खतरों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करें।[18]

कोविड -19 पर जी-20 की प्रतिक्रिया

जी-20 या 20 का समूह एक सक्रिय वैश्विक बहुपक्षीय मंच रहा है जिसमें ग्लोबल नॉर्थ और साउथ शामिल हैं, जो वित्त, विकास और सुरक्षा मुद्दों पर एक प्रमुख निर्णय निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

कोविड -19 के जवाब में जी-20 का व्याख्यान और फोकस

जी-20, वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ), इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (आईएमएफ), वर्ल्ड बैंक ग्रुप (डब्ल्यूबीजी), यूनाइटेड नेशंस (यूएन) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर अपने वर्तमान जनादेश के भीतर महामारी पर काबू पाने के लिए जो करता है, वह उसे करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी-20 व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कोई कमी न छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है:

- लोगों के जीवन की रक्षा करना ।
- लोगों की नौकरियों और आय की रक्षा करना ।
- विश्वास की पुनः स्थापना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, विकास को पुनर्जीवित करना और मजबूती से उभरना ।
- व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अवरोधों को कम करना ।
- सभी जरूरतमंद देशों को सहायता प्रदान करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और वित्तीय उपायों पर समन्वय।

महामारी से लड़ाई

जी-20 सभी आवश्यक स्वास्थ्य उपाय करने और महामारी को रोकने और लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना का समय पर साझाकरण और पारदर्शिता; महामारी विज्ञान और क्लीनिकल डेटा का आदान-प्रदान; शोध और विकास के लिए आवश्यक सामग्री साझा करना; और विश्व स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, जिसमें डब्ल्यूएचओ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर 2005) के पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन करना शामिल है। चिकित्सा आपूर्ति की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार करना और यह सुनिश्चित करना कि इन्हें व्यापक रूप से, सस्ती कीमत पर एवं समान आधार पर जितनी जल्दी हो सके उपलब्ध कराया जाए, जहां इनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो । इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान जनता के लिए जिम्मेदार संचार के महत्व पर जोर देते हुए, जी-20 हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों को राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अप्रैल में उनकी मंत्रिस्तरीय बैठक द्वारा संयुक्त रूप से महामारी का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्यों का एक सेट आवश्यक रूप से विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है।

फ्रंट-लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, चिकित्सा आपूर्ति की डिलीवरी, विशेष रूप से इलाज के उपकरण, उपचार, दवाएं और टीके सहित, महामारी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में डब्ल्यूएचओ के जनादेश के समन्वय और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से सहयोग करता है एवं प्रतिबद्ध है। कोविड -19 संकट से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों को तेज करने के लिए तत्काल अल्पकालिक कार्रवाई की आवश्यकता को स्वीकार करता है। डब्ल्यूएचओ की रणनीतिक तैयारी और प्रतिक्रिया योजना में वित्तपोषण के अंतर को ख़त्म करने के लिए जी-20 जल्द और हितधारकों के साथ काम करेगा। डब्ल्यूएचओ के कोविड -19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन (सीईपीआई) और गवि - वैक्सीन एलायंस को स्वैच्छिक आधार पर तत्काल संसाधन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी-20 सभी देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र, परोपकारी लोगों और व्यक्तियों से इन प्रयासों में योगदान करने का आवाहन करता है।

[17] AC-A-Global-Strategy-for-Shaping-the-Post-COVID-19-World.pdf (atlanticcouncil.org)
[18] Tackling Covid-19 over the long term | The Institute for Government

सुरक्षित भविष्य के लिए, जी-20 हमारी महामारी संबंधी तैयारियों के खर्च में वृद्धि करके संभावित संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सभी की सुरक्षा को बढ़ाएगा, विशेष रूप से कमजोर समूह जो संक्रामक रोगों से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। जी-20 टीकों और दवाओं के लिए शोध और विकास निधि बढ़ाने, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और मिलकर काम करने से वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी-20, प्रभावकारिता, सुरक्षा, इक्विटी, पहुंच और सामर्थ्य के उद्देश्यों का पालन करते हुए, इलाज, एंटीवायरल दवाओं और टीकों के तेजी से विकास, निर्माण और वितरण की दिशा में निजी क्षेत्र के साथ समन्वय को भी मजबूत करेगा।

जी-20 संबंधित संगठनों के सहयोग से, डब्ल्यूएचओ द्वारा महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया पर एक वैश्विक पहल स्थापित करने की दृष्टि, से आने वाले महीनों में तैयारियों में अंतराल का आकलन करने और वित्त तथा स्वास्थ्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक की रिपोर्ट करने का अनुरोध करता है। यह वैश्विक तैयारियों में प्राथमिकताओं के एकीकरण के लिए वर्तमान कार्यक्रमों में वित्त, टीके और उपचार के विकास और वितरण में तेजी लाने में एक सार्वभौमिक, कुशल, निरंतर वित्त पोषण और समन्वय मंच के रूप में कार्य करेगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का संरक्षण

जी-20 महामारी से आर्थिक और सामाजिक नुकसान को कम करने, वैश्विक विकास को पुनः स्थापित करने, बाजार में स्थिरता बनाए रखने और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए सभी उपलब्ध नीतिगत साधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जी-20 के अनुसार, वह वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्काल और सशक्त उपाय कर रहा है। श्रमिकों, व्यवसायों-विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कमजोर वर्ग को संरक्षित कर रहा है। महामारी के सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय प्रभावों का मुकाबला करने के लिए जी-20 लक्षित राजकोषीय नीति, आर्थिक उपायों और गारंटी योजनाओं के हिस्से के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से अधिक राशि प्रदान कर रहा है।

जी-20 उत्साहिक रूप से और बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता देना जारी रखेगा। संगठित जी-20 कार्य इसके प्रभाव को विकसित करेगा, सुसंगतता सुनिश्चित करेगा और उसे सहयोग करेगा। इस प्रतिक्रिया का विस्तार और व्यापकता वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर वापस लाएगी और नौकरियों में सुरक्षा और विकास की पुनः स्थापना के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करेगा। जी-20 ने हमारे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को कोविड -19 के लिए कार्य योजना विकसित करने में नियमित समन्वय और उचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता को तेजी से वितरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा।

जी 20 केंद्रीय बैंकों द्वारा उनके जनादेश के अनुरूप किए गए असाधारण कार्यवाही का सहयोग करता है। केंद्रीय बैंकों ने घरों और व्यवसायों को ऋण प्रवाह में सहयोग करने, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजारों में नकदी बढ़ाने के लिए कार्य किया है। जी-20 हमारे केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए स्वैप लाइन के विस्तार का स्वागत करता है। जी-20 नियामक और निरीक्षात्मक उपायों का समर्थन करता है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ऐसे उपायों के समन्वय स्वागत करता है जिससे वित्तीय तंत्र द्वारा अर्थव्यवस्था का सहयोग बना रहे।

जी-20 एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में सभी उपकरणों का पूरी तरह से उपयोग करने वाले देशों का सहयोग करने के लिए आईएमएफ और डब्ल्यूबीजी द्वारा उठाए गए कदमों का भी स्वागत करता है और उनसे महामारी के प्रभावों, नीति सुझावों और प्रतिक्रिया पर नियमित रूप से जी-20 को अपडेट करने के लिए कहता है। जी 20 महामारी के कारण घटती आय वाले देशों में ऋण असुरक्षा के जोखिमों को सम्बोधित करता रहेगा। जी-20 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) से रोजगार पर महामारी के प्रभाव का निरिक्षण करने के लिए भी कहता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवधानों को संबोधित करना

हमारे नागरिकों की जरूरतों के अनुसार, जी-20 महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति, दुर्लभ कृषि उत्पादों, और अन्य वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को सीमा पार सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों को हल करने के लिए, लोगो के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सहयोग करेगा ।

जी-20 अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय यातायात और व्यापार में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने के तरीकों का समन्वय करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से लक्षित, अनुपातिक, पारदर्शी और अस्थायी आपातकालीन उपाय करने होंगे। जी-20 ने अपने व्यापार मंत्रियों को व्यापार पर महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन करने का काम दिया है।

जी-20 स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, पूर्वानुमानित, स्थिर व्यापार और निवेश के लिए वातावरण बनाने तथा बाजारों के स्वतंत्र संचालन के लिए कार्यरत है।

वैश्विक सहयोग को बढ़ाना

जी-20 फ्रंट लाइन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेष रूप से डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, डब्ल्यूबीजी, बहुपक्षीय संगठनों और क्षेत्रीय विकास बैंकों के साथ एक मजबूत, सुसंगत, समन्वित और तीव्र वित्तीय पैकेज तैयार करने और उनके साधनो में अंतराल को दूर करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से काम करेगा। जी-20 वैश्विक वित्तीय सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए तैयार है। जी-20 कोविड -19 के कारण स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक संकटो से उभरते विकासशील देशों का सहयोग करने के लिए इन सभी संगठनों को निजी क्षेत्र के साथ समन्वय करके काम करने का अनुरोध करता है।

जी 20 उन सभी देशों के लिए चिंतित है, जो गंभीर संकटों, स्वास्थ्य तंत्र और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने में कम सक्षम है, विशेष रूप से विकासशील और कम विकसित देश, जैसे कि अफ्रीका और छोटे द्वीप। इसके साथ ही वे उनके शरणार्थियों एवं विस्थापित व्यक्तियों द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियों के लिए भी चिंतित हैं। जी-20 का मानना है कि अफ्रीका की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना विश्व स्वास्थ्य की कुंजी है। जी-20 क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता को मजबूत करेगा, विशेष रूप से खतरे में रह रहे समुदायों के लिए। जी-20 विकास और मानवीय वित्तपोषण जुटाने के लिए तैयार है।

जी-20 नोट करता है कि संबंधित शीर्ष अधिकारियों को महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों का सहयोग एवं समन्वय करना होगा, जिसमें राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सीमा प्रबंधन के उपाय और नागरिकों को उनके देश भेजने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना शामिल है।

जी-20 तत्काल प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है । जी 20 स्थिति अनुसार अपनी तत्परता व्यक्त करता है। इस महामारी से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई, एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। जी 20 को विश्वास है कि, मिलकर काम करते हुए, जी 20 इससे उभर जाएगा। जी 20 मानव जीवन की सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक स्थिरता की पुनः स्थापना और मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास के लिए ठोस नींव रखेगा।[19]

जी-20 द्वारा विकास पर केंद्रीयकरण[20]

विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिम्मेदार जी-20 मंत्रियों ने पहली बार इटैलियन जी-20 प्रेसीडेंसी के तहत मुलाकात की और एक महत्वाकांक्षी, ठोस, कार्यवाही योग्य, समन्वित और प्रतिबद्ध वैश्विक कोविड-19 प्रतिक्रिया जो विकासशील देशों को वर्तमान स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और सभी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रयास करते हुए सामाजिक आर्थिक संकट से उभरने में मदद करने के लिए कहा। दीर्घकालीन विकास के लिए 2030 एजेंडा और इसके दीर्घकालीन विकास लक्ष्य (एसडीजी), अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (एएएए), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और पेरिस समझौता आधिकारिक बयान के लिए हमारे आवश्यक संदर्भ हैं क्योंकि वे एक समावेशी, लचीला, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण ब्लू प्रिंट (नक़्शे) में स्थायी रूप से सुधार को आकार देने के लिए साझा किये गए। जी-20 2030 एजेंडा और जी-20 कार्य योजना का 2030 एजेंडा समय अनुसार और महत्वाकांक्षी रूप से कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें जी-20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप (डीडब्ल्यूजी) अभिभावक है। जी-20 ने संकट में तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान की, जिसमें जी-20 देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए सहायता, कोविड-19 राहत और पुनः स्थापना के लिए सहयोग, आवश्यक वित्तीय पैकेज, खाद्य सुरक्षा प्रणाली, पोषण शामिल है, खाद्य सुरक्षा, पोषण और खाद्य प्रणालियों पर 2021 मटेरा घोषणा, और मई 2021 में रोम में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के अंतर्गत। जी-20 2021 वैश्विक मानवीय अवलोकन के माध्यम से कोविड -19 महामारी के तत्काल मानवीय परिणामों को संबोधित करने के महत्व को दोहराते हैं और जी-20 ब्रिंडिसि के सहयोग से मानवतावाद पर इटालियन प्रेसीडेंसी और डब्ल्यूएफपी द्वारा सह-संगठित जी-20 मंत्रिस्तरीय कार्यक्रमो का स्वागत करता हैं।

संकट ने 2030 एजेंडा के दीर्घकालीन विकास की प्रगति को पीछे कर दिया है और इसने प्रभावों को और दूर कर दिया है, जिसमें शिक्षा, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा, और लैंगिक समानता, विशेष रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्थायी सुधार का आधार तैयार करना, जो हर क्षेत्र में सभी दीर्घकालीन विकास लक्ष्यो को गति प्रदान करे, गरीबी और कुपोषण को सभी रूपों में समाप्त करना, अच्छी नौकरियों का सृजन करना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, असमानताओं को कम करना और उन्हें संबोधित करना, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के कारण और परिणाम, भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय प्रवाह का विरोध करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह

[19] Extraordinary G20 Leaders' Summit statement on COVID-19 | Prime Minister of Canada (pm.gc.ca)
[20] G20 Development Ministers meeting (international.gc.ca)

संस्थानों का विकास करना। जी-20 सभी विकासशील देशों और क्षेत्रों का सहयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित है क्योंकि वे स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संकट और प्रभावों का सामना करते हैं, कम विकसित देशों और छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और अफ्रीका में विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करते हैं। एक स्थिर और स्थायी वैश्विक सुधार के लिए महामारी पर काबू पाना सबसे पहली शर्त है। कोविड-19 महामारी की नई लहरों और दुनिया भर में टीकाकरण के अलग-अलग पैमाने और गति के साथ, देशों में रिकवरी असमान है। इस सन्दर्भ में, जी-20 एक वैश्विक सार्वजनिक कल्याण के रूप में व्यापक कोविड-19 टीकाकरण की भूमिका की पुष्टि करता है और सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते कोविड-19 उपकरणों (टीके, चिकित्सा विज्ञान, निदान, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) के लिए वैश्विक और समान पहुंच बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता को दोहराता है।

एसडीजी पर ध्यान दें- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जी-20 को एक सक्षम नीतिगत वातावरण को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और सभी संभावित संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संकट से उबारने के लिए कार्यवाही और दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रयासों का सहयोग करना चाहिए। इटैलियन जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, जी-20 दीर्घकालीन विकास के लिए वित्त जुटाने, उसके उपयोग और वित्तपोषण को संरेखित करने और स्थानीय स्तर पर एसडीजी को प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ शहरों की भूमिका को मजबूत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे है।

कोविड -19 के लिए जी-20 की वित्तीय प्रतिक्रिया

इस अभूतपूर्व संकट में, सरकारों ने व्यक्तियों को सीधे भुगतान से लेकर संघर्षपूर्ण व्यवसायों के लिए "असीमित" ऋण तक, बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता का वादा किया। 26 मार्च के अप्रत्यक्ष शिखर सम्मेलन में, प्रमुख ग्रुप टवेंटी (G20) अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कहा कि वे सामाजिक, आर्थिक, और महामारी के वित्तीय प्रभावो पर 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर रहे हैं, जो 2019 जी-20 देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.4 प्रतिशत के बराबर है । सीएसआईएस ने आर्थिक संकट का जवाब देने के लिए जी-20 देशों द्वारा की गई प्रमुख वित्तीय कार्रवाइयों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया।

कई प्रमुख रुझान सामने आते हैं:

10 अप्रैल से बढ़ी वित्तीय सहायता: जी-20 का अनुमान है कि 29 अप्रैल तक जी-20 देश वित्तीय सहायता में 6.3 ट्रिलियन डॉलर प्रदान करेंगे, जो 2019 की जी-20 जीडीपी के 9.3 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, 3.2 ट्रिलियन डॉलर प्रत्यक्ष सरकारी खर्च (2019 जी-20 जीडीपी का 4.8 प्रतिशत) का सहयोग, जो 10 अप्रैल तक 2.1 ट्रिलियन डॉलर (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) था। ऋण वृद्धि 2.3 ट्रिलियन डॉलर और कर राहत में 0.8 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करते हैं।

जी-20 ऋण गारंटी संरचना अकेले 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है: यूरोपीय देशों के नेतृत्व में जी-20 अर्थव्यवस्थाओं ने 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के ऋण गारंटी ढांचे की घोषणा की है, जो 2019 जी-20 जीडीपी का 3 प्रतिशत है। यह देखा गया है कि कई गारंटी ढाँचे पूर्व निर्धारित वित्तीय व्यय मात्रा जुटा नहीं पाते, जी-20 आंकड़ों की गारंटी के लिए 50 प्रतिशत "राजकोषीय मूल्य" प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप हमारे मुख्य वित्तीय सहयोग का आंकड़ा 6.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। ऋण गारंटी के लिए 100 प्रतिशत "राजकोषीय मूल्य" निर्दिष्ट करने से हमारा मुख्य आंकड़ा बढ़कर 7.4 ट्रिलियन डॉलर अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 10.8 प्रतिशत हो जाएगा। इसके विपरीत, ऋण गारंटी के लिए शून्य "राजकोषीय मूल्य" निर्दिष्ट करने से हमारा मुख्य आंकड़ा 5.3 ट्रिलियन डॉलर अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 7.8 प्रतिशत कम हो जाएगा।

उभरते बाजार (ईएम) अर्थव्यवस्थाओं ने खर्च को बढ़ावा दिया है, लेकिन अभी भी उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) के समकक्ष एक व्यापक अंतर है: जी-20 ईएम राजकोषीय सहयोग 29 अप्रैल तक औसत जीडीपी का 3.2 प्रतिशत, 10 अप्रैल को 1.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि थी, लेकिन अभी भी काफी नीचे है, एई के लिए औसत 11.6 प्रतिशत होना चाहिए । चीन की 2.3 ट्रिलियन युआन (326 बिलियन डॉलर) की घोषणा से स्थानीय सरकार के विशेष प्रयोजन बांड जारी करने पर उसकी राजकोषीय प्रतिक्रिया जीडीपी के 3.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो अभी भी वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान प्रदान की गई राशि से काफी कम है।

वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा संघटक व्यवसायों को वित्तपोषण प्रदान करना है: जी-20 देशो ने 10 अप्रैल 2020 तक वित्तीय सहायता में 5.3 ट्रिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया है, जो 2019 जी-20 जीडीपी का 7.8 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, 2.5 ट्रिलियन डॉलर ऋण वृद्धि (2019 जी-20 जीडीपी का 3.7 प्रतिशत) का सहयोग करेगा, जबकि इसकी तुलना में प्रत्यक्ष सरकारी खर्च में 2.1 ट्रिलियन डॉलर (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) और कर राहत में 0.6 ट्रिलियन डॉलर (0.9 प्रतिशत) (हमारे विश्लेषण में कर टालना शामिल नहीं है) । लगभग सभी सहयोग नई मांग और निवेश को प्रोत्साहित करने के बजाय कंपनियों और व्यक्तियों को बचाए रखने पर केंद्रित हैं, जो स्वास्थ्य प्रतिबंधों में ढील से प्राथमिकता बन जाएगी।

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान अभी तक प्रत्यक्ष सरकारी खर्च स्तर से अधिक है: प्रत्यक्ष सरकारी खर्च में 2008-2009 में जी-20 जीडीपी के 2.5 प्रतिशत, जो जीएफसी के लिए किये गए "संकट से संबंधित समझदार उपाय" की तुलना में जी-20 2019 जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है। महामारी के अंत तक, जी-20 देशों ने जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफसी में जितना खर्च किया था, उससे कहीं अधिक खर्च करने की संभावना है।

जीएफसी की तुलना में जी-20 देशों ने तेज़ी से प्रतिक्रिया दी है: महामारी के जवाब में, जी-20 सरकारों ने फरवरी और अप्रैल की शुरुआत के बीच राजकोषीय सहयोग में लगभग 8 प्रतिशत जीडीपी की घोषणा की, जो आने वाले हफ्तों और महीनों में और अधिक होने की उम्मीद है।

ईएम अर्थव्यवस्थाएं अधिक विवश हैं: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, जी-20 के ईएम सदस्यों ने एई जी-20 सदस्यों की तुलना में बहुत कम वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जो आंशिक रूप से अधिक बाध्यकारी वित्तपोषण बाधाओं को दर्शाता है। 10 अप्रैल तक जी-20 ईएम राजकोषीय सहयोग सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत बनाम जी-20 एई के बीच 11.7 प्रतिशत है। कई ईएम अर्थव्यवस्थाएं एई की तुलना में महामारी के पहले चरण में हैं और उन्हें आवश्यक राहत उपायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वित्तपोषण की आवश्यकता है।[21]

जी-20 द्वारा विकास प्रतिक्रिया

अब तक जी-20 की महामारी पर प्रतिक्रिया के प्रयास - विशेष रूप से ऋण सेवा निलंबन पहल और डीएसएसआई से परे ऋण उपचार के लिए सामान्य रूपरेखा - कम आय वाले देशों तक सीमित हैं। विकास के पक्षसमर्थक, समाज सेवी संगठन और संघर्षपूर्ण मध्यम आय वाले देश जी -20 और आईएमएफ सहित अन्य वैश्विक संगठनों को सहयोग के लिए पात्र देशों के समूह को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

विज्ञप्ति (सरकारी बयान) में कई बार "कमजोर" देशों का सहयोग करने का उल्लेख किया गया है, न केवल कम आय वाले देशों के लिए, संभावित रूप से कुछ मध्यम-आय वाले देशों के लिए कार्यक्रमों का विस्तार, जो विशेष रूप से महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकारें "समय से पहले राहत उपायों को वापस लेने" से बचने के लिए सहमत हुईं और विनिमय दरों पर प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा। समूह ने अंतर्राष्ट्रीय कर संरचना पर एक हालिया समझौते का भी समर्थन किया, जिसमें बहुराष्ट्रीय उद्यमों के मुनाफे और एक प्रभावी वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर शामिल है। जलवायु पर, जी -20 ने सहमति व्यक्त की कि "करीबी अंतरराष्ट्रीय समन्वय" महत्वपूर्ण था और सरकारों को नीतियों और उपकरणों के मिश्रण पर ध्यान देना चाहिए। ताकी "सबसे गरीब और कमजोर देशो" को "लक्षित" सहायता प्रदान की जाये।[22]

एसडीजी का स्थानीयकरण

एसडीजी स्थानीयकरण प्रक्रिया 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन को बॉटम-अप (नीचे से ऊपर की ओर) दृष्टिकोण के माध्यम से बढ़ाना आवश्यक है। एसडीजी का स्थानीयकरण स्थानीय स्तर पर वैश्विक लक्ष्यों के अनुकूलन और वैश्विक चुनौतियों के लिए स्थानीय स्तर पर समाधान खोजने के बारे में

है। इसके लिए, राष्ट्रीय संरचना को एसडीजी रणनीतियों को विकसित करने और नेतृत्व करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओ को सशक्त बनाना चाहिए। ग्रामीण-शहरी संपर्क की परिवर्तनकारी क्षमता और एसडीजी के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय विकास योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा क्षेत्रीय दृष्टिकोणों पर कम ध्यान दिया जाता है। क्षेत्रीय नीतियों को अक्सर एक स्थानिक लेंस के बिना (स्थानीय समस्याओ को समझे बिना) लागू किया जाता है और ग्रामीण और शहरी विकास को एक दूसरे से अलग-थलग कर दिया जाता है। हाल ही में जी-20 पहल जैसे ग्रामीण युवा रोजगार (2017), क्षेत्रीय योजना के माध्यम से सतत आवास पर जी-20 उच्च स्तरीय सिद्धांत (2018) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए गुणवत्ता बुनियादी ढांचे पर जी-20 दिशानिर्देश (2020) ने क्षेत्रीय विकास को संबोधित करने के लिए आधार तैयार किया और एसडीजी के स्थानीयकरण को आगे बढ़ाया।[23] [24]

हालाँकि, जी-20 द्वारा अपनाए गए पथ को लेकर चिंताएँ हैं, विशेष रूप से पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौतों के अनुसार उनके फॉसिल (जीवाश्म) ईंधन को चरणबद्ध करने के तरीके पर।[25] महत्वपूर्ण रूप से सार्थक समाधानों को प्रभावी ढंग

[21] Taken from Breaking down the G20 Covid-19 Fiscal Response | Center for Strategic and International Studies (csis.org)
[22] How the COVID-19 response fared at the G-20 | Devex
[23] Agenda-UNDP-OECD-5th-G20-DWG-Workshop.pdf
[24] The need for data innovations in the time of COVID-19 — SDG Indicators (un.org)
[25] G20 Backtracks on Fossil Fuel Funding Phase-Out in COVID-19 Recovery - Oil Change International (priceofoil.org)

से तैयार करने के लिए जी-20 की आलोचना की गई है जो दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरने वाले एकतरफा निर्णयों के एक सेट की तुलना में अधिक वैश्विक सहयोग के बारे में सूचित करता है।[26]

विकास के लिए जी 20 की कार्रवाई पर सिविल सोसायटी की प्रतिक्रिया

सिविल सोसाइटी (समाज सेवी क्षेत्र) ने जी-20 को स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है जो कि कोविड के समय में बढ़ गए हैं। इसके साथ, विकास के एजेंडे को भी नुकसान हुआ है और भ्रष्टाचार और गलत कार्यो के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के बिना वर्तमान अपराधों को बढ़ा सकता है।[27]

जी-20 के लिए सी-20 का मुख्य संदेश[28]

सी-20 ने जी-20 नेताओं को "स्वास्थ्य बाजार" खोलने के लिए विदेशी निवेशकों और प्रतिस्पर्धा के लिए व्यापार समझौते की बातचीत में चल रहे प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी, जिसने स्वास्थ्य प्रणालियों को एक और निवेश अवसर में बदल दिया। जी-20 को चिंता है कि स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठाने में सक्षम और असक्षम लोगो के बीच का अंतर और बढ़ जायेगा।

सी-20 ने चेतावनी दी है कि प्रकोप के परिणामस्वरूप असमानताएँ बढ़ेंगी। कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रम नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है, जो घर पर बैठ नहीं सकते हैं, और जो गरीबी में अपेक्षित वृद्धि के लिए तैयार हैं, विशेष रूप से उच्च अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है।

दुनिया को आर्थिक संकट के लिए बहुपक्षीय समन्वय के साथ प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है जो सट्टा गतिविधियों से नकदी के दुरुपयोग को रोककर पर्याप्त वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। उचित रूप से डिज़ाइन किए गए प्रोत्साहन पैकेज में न केवल व्यवसायों और एसएमई के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि घरेलू, श्रमिकों और कमजोर वर्ग को भी ध्यान में रखना चाहिए।

बहुआयामी समस्या के लिए कई कर्ताओ द्वारा समाधान की आवश्यकता होती है। एफएटीएफ नियमों का पालन करने में समाज सेवी क्षेत्र और एनजीओ के सदस्यों को बैंकों द्वारा जोखिम और लागत से बचने के कारण कड़े वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह का वित्तीय बहिष्कार वैश्विक आपातकालीन स्थितियों का जवाब देने की हमारी क्षमता को सीमित करता है।

कोविड -19 पर ब्रिक्स की प्रतिक्रिया

ब्रिक्स देशों में पांच उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जो जी-20 का हिस्सा हैं। ब्रिक्स अपने स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बहु-क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और वित्त के मुद्दों को आगे बढ़ाता है।

कोविड -19 पर ब्रिक्स (भारत की अध्यक्षता में) द्वारा निर्धारित किए गए प्रमुख क्षेत्र[29]

ब्रिक्स ने माना है कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियां, विशेष रूप से कोविड -19 महामारी, राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता के लिए एक शक्तिशाली स्मारक हैं। डब्ल्यूएचओ, सरकारों, गैर-लाभकारी संगठनों, शिक्षा संस्थानों, व्यापार और उद्योग द्वारा महामारी का मुकाबला करने के लिए किए गए उपायों को स्वीकार करते हुए, वे यह भी उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोविड -19 महामारी और अन्य वर्तमान और भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियो से लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ की नीतिगत प्रतिक्रियाओं में सुधार और मजबूती करेगा।

इस महामारी को समाप्त करने और तत्काल, समावेशी, टिकाऊ और लचीली पुनः स्थापना (रिकवरी) को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य कल्याण के रूप में कोविड -19 के विरुद्ध व्यापक टीकाकरण की भूमिका को मान्यता दी गई थी, और इसके संदर्भ में विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड -19 टीकों के तत्काल विकास और तैनाती को रेखांकित किया, और एक विविध वैक्सीन पोर्टफोलियो के लिए विभिन्न हितधारकों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया।

---

[26] Missing in action: The G20 in the Covid crisis (lowyinstitute.org)
[27] COVID-19 crisis demands actions not words from G20… - Transparency.org
[28] B20-C20-L20-T20-W20-Y20-Joint-Statement.pdf (civil-20.org)
[29] BRICS Joint Statement on Strengthening and Reforming the Multilateral System (mea.gov.in)

समय पर, सस्ती और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपचार, चिकित्सा विज्ञान, दवाओं, टीकों और आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों एवं उनके घटकों के साथ उपकरणों के वितरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कोविड -19 महामारी का मुकाबला करना और निवारण उपायों और कार्यों सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की उपलब्धि का सहयोग करना। महामारी के दौरान सभी प्रासंगिक उपायों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, जिसमें एक कोविड -19 वैक्सीन बौद्धिक संपदा अधिकार छूट पर विश्व व्यापार संगठन में चल रहे विचार का समर्थन करना और ट्रिप्स समझौते के लचीलेपन का उपयोग और ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा शामिल है। ब्रिक्स ने टीके की खुराक साझा करने, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के विकास, स्वास्थ्य उत्पाद और आवश्यक इनपुट और चिकित्सा उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास, मूल्य पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को दोहराया और उन उपायों के कार्यान्वयन में उचित संयम बरतने का आह्वान किया जो टीकों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आतंकवाद का मुकाबला करने और कोविड -19 के लिए वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया।[30]

कोविड -19 प्रतिक्रिया के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का विकास वित्तपोषण

कोविड -19 के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक संकट ने तेजी से बड़े पैमाने पर और अभूतपूर्व रूप से प्रभावित किया है। इसके लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने अपने ऋण कार्यक्रम को फिर से तैयार किया और ब्रिक्स को महामारी के विरुद्ध सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता के लिए साहसपूर्ण प्रतिक्रिया दी। संकट के तुरंत बाद, एनडीबी ने ऋणों के प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और वितरण के लिए अधिक लचीली और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के साथ 10 बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता कार्यक्रम की घोषणा की। सामान्य परिस्थितियों में, एक संरचना परियोजना के लिए ऋण के वितरण में कई महीने लग सकते हैं। कोविड -19 संबंधित सहायता ऋण स्वीकृत होने के तीन से चार सप्ताह के भीतर भुगतान बुलेट के रूप में भुगतान किया गया।[31] दूसरे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) कोविड-19 रिस्पांस बॉन्ड का उपयोग एनडीबी के सदस्य देशों में दीर्घकालीन विकास गतिविधियों के वित्तपोषण के साथ ब्रिक्स सदस्य देशों को आपातकालीन सहायता ऋण के लिए किया जाएगा। यह दीर्घकालीन विकास और कोविड के बाद की रिकवरी को सहयोग करने के लिए बांड वित्त का भी उपयोग कर रहा है।[32] इस तरह के आपातकालीन ऋणों का उपयोग प्रत्यक्ष खर्चों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है जैसे कि कोविड -19 संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदना या सरकारी उपायों को सहायता प्रदान करना जैसे कि एनडीबी सदस्य देशों में आय राहत उपायों तथा आर्थिक सुधार में योगदान करना। ब्राजील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका को पहले ही फंड मिल चुका है।[33] बॉन्ड इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग एनडीबी के सदस्य देशों में दीर्घकालीन विकास गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा, जिसमें बैंक द्वारा सदस्य देशों को आपातकालीन सहायता ऋण देना भी शामिल है। इस तरह के आपातकालीन ऋणों का उपयोग कोविड -19 के प्रकोप के खिलाफ लड़ाई से संबंधित प्रत्यक्ष खर्चों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है या एनडीबी के सदस्य देशों में आर्थिक सुधार में योगदान करने वाले सरकारी उपायों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है

केंद्रीय बैंकों और आधिकारिक संस्थानों की मजबूत भागीदारी के साथ लेनदेन की असाधारण उच्च गुणवत्ता वाले निवेशको को समर्थन मिला, जो आवंटन के 75% का प्रतिनिधित्व करता था। अंतिम बॉन्ड बुक का निवेशक भौगोलिक वितरण इस प्रकार था: 56% - एशिया, 29% - ईएमईए, 15% - अमेरिका।[34]

कोविड-19 के लिए फास्ट-ट्रैक (शीघ्र) आपातकालीन प्रतिक्रिया

कोविड -19 के प्रभावों से उत्पन्न होने वाली तत्काल मांगों के लिए आवश्यक है कि इसके लिए शीघ्र सहायता प्रदान की जाये। इसे सक्षम बनाने के लिए, सहायता राशि के प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), स्वीकृति और वितरण के लिए एमडीबी द्वारा फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, चूंकि प्रभावों की गंभीरता और अपनाए गए उपायों के आधार पर आपातकालीन सहायता की आवश्यकताएं एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकती हैं, इसलिए देश विशेष होने के लिए प्रतिक्रिया को लचीला बनाने की भी आवश्यकता होगी। इसलिए, एनडीबी की आपातकालीन प्रतिक्रिया में गति और लचीलेपन की विशेषता होगी। नीति अनुसार वर्तमान प्रावधान एनडीबी नीतियों और जीसी की आवश्यकताओं से भिन्न हैं, इस नीति के प्रावधानों को सुविधा के अनुसार एनडीबी की कोविड-19 की आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

कोविड -19 आपातकालीन कार्यक्रम ऋण (सीईपीएल) - सीईपीएल, कोविड -19 प्रभावों को संबोधित करने के लिए विभिन्न उपायों से युक्त सरकारी कार्यक्रमों के सहयोग से सार्वभौमिक आपातकालीन सहायता प्रदान करेगा। बी -

[30] Brics Summit: Fighting terrorism and global COVID-19 pandemic to be the focus tomorrow - The Financial Express
[31] COVID-19: How multilateral development banks can lead through a crisis | World Economic Forum (weforum.org)
[32] NDB's US$1.5 billion bond targets sustainability, Covid relief | The Asset
[33] BRICS New Development Bank issues second COVID-19 Response bond | The BRICS Post
[34] NDB prices inaugural USD 1.5 billion 3-year COVID Response Bond in international capital markets - New Development Bank

प्रयोजन - सीईपीएल कोविड-19 से प्रभावित एमसी को सहयोग करेगा (i) कोविड-19 का पता लगाने, परीक्षण करने, इलाज करने, रोकथाम करने और बीमारी को समाप्त करने के लिए और भविष्य के आपातकालीन संकटो का जवाब देने और रोकने की क्षमता को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य उपाय करने के लिए सहयोग करेगा; (ii) कोविड-19 के संकट से उत्पन्न होने वाले तत्काल सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना, और (iii) तत्काल अर्थव्यवस्था में सुधार के उपाय करना।[35]

दक्षिण अफ्रीका को सहयोग

19 जून, 2020 को, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के निदेशक मंडल ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार को 1 बिलियन अमरीकी डालर के कोविड 19 आपातकालीन कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी। "दक्षिण अफ्रीका को कोविड -19 आपातकालीन कार्यक्रम ऋण तत्काल अनुरोध और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के तत्काल वित्तपोषण की जरूरतों के जवाब में प्रदान किया जाएगा। एनडीबी की सहायता का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में कमजोर आबादी के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने और महामारी पर काबू पाने के लिए तत्काल स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा । यह ऋण दक्षिण अफ़्रीकी सरकार को नोवेल कोरोनावायरस रोग-19 के लिए स्वास्थ्य सेवा शुरू करने और कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक प्रभाव को कम करके एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने में सहायता करेगा। कार्यक्रम में कोविड -19 से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को रोकने, जांचने और उपचार के लिए किए गए उपायों से प्रभावित कमजोर समूहों को सामाजिक अनुदान प्रदान करने पर विचार किया गया है।[36]

भारत को सहयोग

आज भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) और ग्रामीण संरचना संबंधित भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत 'कोविड-19 से भारत के आर्थिक सुधार और व्यय सहयोग के लिए 1,000 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। लोगों के यात्रा करने पर देशभर में प्रतिबंध, राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कड़े प्रतिबंधों और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए थोड़े थोड़े समय में स्थानीय लॉकडाउन के साथ घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित हुई, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गई। इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के रोजगार और आय का नुकसान हुआ। यह कार्यक्रम सरकार को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को सक्षम करने में मदद करेगा: कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट का मुकाबला करने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य जो ग्रामीण मांग को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करेगा । कार्यक्रम में एनआरएम से संबंधित टिकाऊ ग्रामीण संरचना का निर्माण और ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रस्ताव है, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों से लौटे हैं और कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका खो चुके हैं। यह कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में भारत सरकार के प्रयासों का सहयोग करेगा और एनआरएम कार्यों और रोजगार सृजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को सक्षम करेगा। कोविड-19 के लिए फास्ट-ट्रैक आपातकालीन प्रतिक्रिया पर एनडीबी की नीति के तहत वित्त पोषण से ग्रामीण आय और व्यय को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप मांग में वृद्धि होगी जो आर्थिक सुधार में सहायता करेगी।[37]

ब्राजील को सहयोग

20 जुलाई, 2020 को, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के निदेशक मंडल ने ब्राजील गणराज्य सरकार को 1 बिलियन अमरीकी डालर के कोविड -19 आपातकालीन कार्यक्रम ऋण की मंजूरी दी। एनडीबी द्वारा प्रदान किए गए संसाधन अनौपचारिक, स्वरोजगार और बेरोजगार श्रमिकों सहित कमजोर परिस्थितियों में लगभग 5 मिलियन लोगों को आय

[35] Policy-on-Fast-track-Emergency-Response-to-COVID-19.pdf (ndb.int)
[36] NDB Board of Directors approves USD 1 billion COVID-19 Emergency Program Loan to South Africafile.html (tralac.org)
[37] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1681118

प्रदान करके ब्राजील की सुरक्षा में मदद करेंगे। । कार्यक्रम द्वारा गारंटिड मूल आय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भोजन और स्वास्थ्य संबंधित सामान, जैसे कि दवाएं और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध कराएगी, जो कि कोविड -19 की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यह ऋण ब्राजील सरकार को यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि संकट से निपटने के लिए मजबूत वित्तीय सहायता उपलब्ध है और प्राथमिकता आधारित निवेश परियोजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे देश के आर्थिक सुधार में योगदान मिलेगा। ब्राजील में एनडीबी की परियोजना पांच बहुपक्षीय विकास बैंकों और विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए आपातकालीन ऋणों की पूरक है - इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी), इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक (आईडीबी), दी डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ लैटिन अमेरिका (सीएएफ), दी जर्मन डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्ल्यू), और दी फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) - जो महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए 4 बिलियन अमरीकी डालर का वित्तपोषण प्रदान करने के प्रयासों में शामिल हुए।[38]

रूस को सहयोग

न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने रूस में कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए 1 बिलियन डॉलर तक के ऋण मंजूरी दी है। एनडीबी की स्थापना ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसे ब्रिक्स के रूप में जाना जाता है। इसने अपने सदस्य देशों को संकट से संबंधित सहायता में 10 बिलियन डॉलर तक प्रदान करने के लिए अप्रैल 2020 में एक आपातकालीन सहायता सुविधा की स्थापना की। यह ऋण कोविड -19 संकट में रूस के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करेगा और देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता और लचीलेपन में सुधार करेगा।[39]

चीन को सहयोग

ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने कोविड -19 महामारी से चीन की आर्थिक रिकवरी को सहयोग करने के लिए 7 बिलियन युआन (लगभग 1.08 बिलियन अमरीकी डालर) के आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी। यह एनडीबी द्वारा चीन को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए स्वीकृत समान राशि का दूसरा आपातकालीन ऋण है। पिछले 7 बिलियन-युआन ऋण का सहयोग और भुगतान 2020 में किया गया था। बैंक के एक बयान में कहा गया है कि चीन को नवीनतम ऋण उत्पादन गतिविधियों की पुनः स्थापना में सहयोग करेगा, रोजगार को स्थिर करेगा, दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।[40]

एनडीबी सहयोगी परियोजनाओं पर जवाबदेही

दीर्घकालीन संरचना और उचित संचालन को बढ़ाने का दावा करने के बावजूद, एनडीबी ने ट्रांसनेट - एक विवादास्पद दक्षिण अफ्रीकी बहुसंख्यक राज्य- जिसका अपना व्यवसाय है - को 200 मिलियन डॉलर का ऋण दिया - डरबन पोर्ट-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए वित्तपोषण किया गया, यह संदेहजनक है कि ऋण प्रदान करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई।

इसके अलावा, एनडीबी ने एसकॉम को 180 मिलियन डॉलर का ऋण देने का निर्णय किया - जो एक ऊर्जा उपभोगिता कंपनी है और जो बुरी तरह से कर्ज और भ्रष्टाचार घोटाले में फसी हुई है। 2018 में ब्रिक्स जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन की शुरुआत में एनडीबी के विरुद्ध चार अफ्रीकी गोल्डमैन पुरस्कार विजेताओं के नेतृत्व में 100 से अधिक पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने एनडीबी परियोजना वित्तपोषण पर चिंताओं और आलोचनाओं को दूर करने के लिए पारदर्शिता और उचित कार्यवाही का अभ्यास करने के लिए प्रदर्शन किया।

अपने वित्तीय तंत्रों में बदलाव के अलावा, सदस्य राज्यों को पाइपलाइन पहलों के कार्यान्वयन पर अमल करने की जरूरत है। हालांकि महामारी का मुकाबला करने, टीकाकरण, टेलीमेडिसिन सहित संयुक्त चिकित्सा कार्यक्रम, ब्रिक्स के एजेंडे में लंबे समय से प्रमुख रहे हैं, लेकिन अतीत में इसका पालन करने में विफलता ने ब्लॉक की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है।[41]

प्रतिरक्षा के लिए टीकाकरण की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता

अतिरिक्त घरेलू क्षमता का विकास, संभवतः अंतरराष्ट्रीय दवा कंपनियों के साथ साझेदारी में टीके विकसित करने और उत्पादन करने के लिए ब्रिक्स के आगे बढ़ाने की दिशा में

[38] NDB approves USD 1 billion COVID-19 Emergency Program Loan to Brazil - New Development Bank
[39] BRICS development bank approves $1 billion loan for Russia's frontline health workers | Reuters
[40] BRICS Bank grants over $1 billion Covid-19 assistance loan to China | Business Standard News (business-standard.com)
[41] Global Health Security: COVID-19 and Its Impacts – BRICS in Time of Pandemic: Leadership from Emerging Economies? | RSIS

कदम है। यह कोविड -19 के विनाशकारी प्रगति में टीकों के लिए उत्तरदायी साबित हुआ है। भविष्य में इसका दीर्घकालीन विकास, लचीली और प्रभावशाली टीके के विकास रणनीतियों पर आधारित होने की संभावना है। यह लोगों को टीके पहुंचाने की बढ़ती हुई क्षमता पर भी निर्भर करेगा - जो निश्चित रूप से एक बार फिर प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व और कुशल सरकारी नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।[42]

सामाजिक-आर्थिक अविकास के कारण कोविड -19 में वृद्धि

ब्रिक्स में अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ और बढ़ती हुई जनसंख्या संक्रमण की दर में तेजी लाने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। कोविड -19 के स्वास्थ्य प्रदर्शन और नीति प्रतिक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक ब्रिक्स देश की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। कोविड -19 महामारी के दौरान भारत, ब्राजील और रूस उच्चतम संक्रमण वाले शीर्ष पांच देशों में से तीन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के साथ। इसके अलावा, 30 अप्रैल, 2021 तक ब्रिक्स देशों में कुल कोविड -19 मामलों में वैश्विक मामलो का एक चौथाई (26.3%) से अधिक था।[43]

कोविड -19 के लिए देशभर में सिविल सोसाइटी की प्रतिक्रिया

महामारी से प्रभावित लोगों के लिए ब्राजील में सकल मूलभूत आय सुनिश्चित करना- एक सकल मूलभूत आय के निर्माण पर दशकों से बहस चल रही थी और महामारी से प्रभावित दुनिया के असमान राष्ट्रों में से एक ब्राज़ील - 160 से अधिक ब्राज़ीलियन सिविल सोसाइटी संगठनों और उनके गठबंधन आंदोलनों ने पिछले महीने इस सिद्धांत को व्यवहार में बदलने के लिए "ऐ रेण्डा बैसिका क्यू क़्यूरेमोस" (द बेसिक इनकम दैट जी-20 वांट) शुरू किया। 20 मार्च को शुरू किया गया यह अभियान तेजी से 500,000 से अधिक नागरिकों द्वारा समर्थन किया गया। इस अभियान ने ब्राजील की राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों को एक विस्तृत नीति प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे तब विधायी एजेंडे में रखा गया था। 30 मार्च को संघीय प्रतिनिधियों और सभासद (बातचीत परिवर्तन के साथ) द्वारा बिल को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।

भारत में राहत और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना- भारत में सिविल सोसाइटी संगठन पहली लहर में आर्थिक तालाबंदी के कारण राहत और खाद्य सहायता प्रदान करने और दूसरी लहर के दौरान महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहे हैं।[44]

चीन में सहायक फ्रंटलाइन वर्कर्स - चीन ने वायरस के प्रसार को नियंत्रित और सीमित करने के लिए सामूहिक प्रयास किया है। हालांकि इन प्रयासों का नेतृत्व राज्य द्वारा किया गया है, सिविल सोसाइटी जैसे स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ), चैरिटी फाउंडेशन और जनता के सदस्यों ने नियंत्रण और रोकथाम के प्रयासों में सहायता एवं सहयोग करने में अनिवार्य रूप से योगदान दिया है। हुबेई और अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन से प्रभावित कमजोर समूहों को फ्रंट लाइन चिकित्सा कर्मियों द्वारा सहायता प्रदान की गयी ।

दक्षिण अफ्रीका में सामुदायिक संघटन - कई सिविल सोसाइटी समूहों को कार्य के लिए प्रेरित करने वाली प्राथमिक आवश्यकता भूख है। शुरू में, कई कार्यकर्ताओं को लगा कि लॉकडाउन के कारण यह एक अल्पकालिक आवश्यकता होगी। लेकिन कई समुदायों में भोजन के लिए संघर्ष बढ़ रहा है। भोजन, शिक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं सहित महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल है। संकट की शुरुआत से, कई सिविल सोसाइटी समूहों का एक बड़ा हिस्सा कोरोनावायरस के प्रसार को धीमा करने में लगा था। लेकिन अब कार्यकर्ता बढ़ते बीमारी के बोझ का भी सामना कर रहे हैं, जिसमें समुदाय-आधारित क्षेत्रों की स्थापना, "सुरक्षित घर" या वायरस से जुड़े अंधविश्वासों से लड़ना शामिल है।[45]

---

[42] Combatting COVID-19: the BRICS in comparative perspective NicoliNattrass, CSSR Working Paper No. 464 July 2021 WP464Nattrass.pdf (uct.ac.za)

[43] Zhu, J., Yan, W., zhu, L. et al. COVID-19 pandemic in BRICS countries and its association with socio-economic and demographic characteristics, health vulnerability, resources, and policy response. Infect Dis Poverty 10, 97 (2021)

[44] Importance Of Civil Society OrganisationsIn Managing Covid-19 Pandemic (outlookindia.com)

[45] civil society's response to emerging public health events in china CORD-Papers-2021-06-28 (Version 1) COVID19 (nist.gov)

निष्कर्ष

कोविड -19 से वैश्विक रिकवरी में समय लगेगा, वायरस के बदलते स्वभाव से आर्थिक स्थिति खतरे में हैं।[46] हालाँकि, ऐसे संकेत हैं कि जी - 20 द्वारा टीकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण कुछ हद तक आर्थिक पुनर्रुद्धार देखने को मिल सकता हैं, लेकिन विकास के लिए और अधिक सहयोग और कार्यो की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में एसडीजी में जो फेर बदल हुआ है, इसकी रिपोर्ट चिंताजनक है, संसाधनों में निवेश और दिशा परीक्षण अब बेमानी हो गया हैं। बहुपक्षीय संगठनों को अहम भूमिका निभानी होगी। जी-20 ने एक आशाजनक प्रस्ताव की शुरुआत की है और 2015 के विकास एजेंडे के बाद एसडीजी के स्थानीयकरण और सिविल सोसाइटी के पक्षसमर्थन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। एसडीजी को स्थानीय बनाने के लिए जी-20 के पास क्या रोडमैप या योजना है, यह अभी सामने नहीं आया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और सिविल सोसाइटी के साथ काम करके एक वैश्विक ढांचा विकसित किया जा सकता है जो 2030 एजेंडा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा ।

हालाँकि, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और एक शुरुआत के रूप में, वैश्विक सुधार हो सकता है, विकास वित्तपोषण और संचालन नीतियों में सुधार को प्राथमिकता देकर, जो महामारी के प्रबंधन में बाधा रही हैं। एक हितधारक के रूप में सिविल सोसाइटी को शामिल करना नीति पूर्व-आवश्यकता के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि सरकारों तक इसकी पहुंच और सहयोग ने उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को पीछे छोड़ दिया है। बहुपक्षीय मंचों के लिए एक कदम यह होगा कि वह नीति संरचना में सिविल सोसाइटी को शामिल करे और उनके अनुभव को चुनिंदा सम्मेलनों और मंचों में प्रथागत सहयोग और सुनवाई तक ही सीमित न रखा जाए। नित्य संवादों से बचना और सिविल सोसाइटी की भागीदारी को बहुपक्षीय संगठनों में एक स्वाभाविक तंत्र बनाना वैश्विक संचालन समुदाय के लिए उपयोगी होगा। स्पष्ट रूप से, जी-20 को संचालन क्षेत्र को आसान बनाने के लिए सिविल सोसाइटी की मांगों को भी सुनना होगा जो इन वर्षो में काफी कम हो गया है और यह भी अनिवार्य करे कि सदस्य देशों को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम वातावरण प्रदान करें।

ब्रिक्स के साथ यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा ढांचा विकसित किया जा सकता है, हालांकि विकास और आपातकालीन राहत के लिए उनका वित्तपोषण प्रशंसनीय है ! उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट और परिणाम दस्तावेज सार्वजनिक ट्रैकिंग और निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऐसे में यह देखना बाकी है कि आने वाले वर्षों में बहुपक्षवाद अपने आप में कैसे सुधार करेगा। जैसा कि सिविल सोसाइटी जी-20 से अपील करता है कि बहुपक्षीय सुधार की प्रक्रिया में, प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए सिविल सोसाइटी के इनपुट को लिया जाना चाहिए। अंत में, बहुपक्षीय संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं और कार्रवाई केवल देश स्तर पर की जा सकती है, इसलिए सरकारों की नागरिकों के प्रति, उनके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट जिम्मेदारी है।

---

[46] South Africa: Civil Society Groups That Mobilised Around COVID-19 Face Important Choices - allAfrica.com
[47] Warning signs for global recovery as Delta dims outlook | Reuters
[48] What a COVID-19 Vaccine Means for the Global Economic Recovery (internationalbanker.com)
[49] COVID-19 Pandemic Demonstrates Multilateral Cooperation Key to Overcoming Global Challenges, President Stresses as General Assembly Concludes Annual Debate | Meetings Coverage and Press Releases (un.org)
[50] Not Without Us: Civil Society's Role in Implementing the Sustainable Development Goals (who.int)

G20 ITALIA 2·0·2·1

BRICS INDIA 2021

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
INDIA

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

www.vaniindia.org

About VANI

As a platform, it promotes voluntarism and creates space for voluntary action. As a network, it attempts to bring about a convergence of common sectoral issues and concerns for building a truly National agenda of voluntary action in the country. It also facilitates linkages of various efforts and initiatives of the voluntary sector.